



डॉ० विशाल कुमार श्रीवास्तव

भारत और इस्राएल के बीच सैन्य सम्बन्ध: एक सैन्य विश्लेषण

असिस्टेंट प्रोफेसर- रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग, डी०ए०वी० पी० जी० कालेज, कानपुर (उ०प्र०) भारत

Received-26.09.2025,

Revised-03.10.2025,

Accepted-10.10.2025

E-mail vksdav1@mail.com

सारांश: आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सैन्य सम्बन्ध किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीतिक शक्ति के प्रमुख आधार होते हैं। भारत और इस्राएल दोनों ही ऐसे राष्ट्र हैं, जिनकी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ जटिल, बहुआयामी और दीर्घकालिक रही हैं। भारत को जहाँ सीमापार आतंकवाद, सीमा विवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, वहीं इस्राएल निरंतर आतंकवादी संगठनों, क्षेत्रीय शत्रुओं और अस्तित्वगत खतरों से घिरा रहा है।

इन्हीं साझा सुरक्षा चिंताओं, व्यावहारिक विदेश नीति और रणनीतिक आवश्यकताओं के कारण भारत और इस्राएल के बीच सैन्य सम्बन्धों का विकास हुआ। आज यह सम्बन्ध केवल हथियारों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी सहयोग, खुफिया साझेदारी और आतंकवाद-रोधी रणनीतियों तक विस्तृत हो चुके हैं। यह लेख भारत-इस्राएल सैन्य सम्बन्धों का एक समग्र सैन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कुंजीशब्द— राष्ट्र की सुरक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी, आयाम, आतंकवादी संगठन, संप्रभुता, बहुआयामी, दीर्घकालिक, रणनीतिक शक्ति।

भारत और इस्राएल के बीच सैन्य संबंध पिछले तीन दशकों में विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली रक्षा साझेदारियों में से एक बन चुके हैं। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह संबंध केवल हथियार खरीद से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, सह-विकास, सह-निर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक पहुँच चुके हैं। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए रणनीतिक आवश्यकता पर आधारित है। भारत के लिए यह चीन और पाकिस्तान से उभरते खतरों के खिलाफ उन्नत तकनीक प्राप्त करने का माध्यम है, जबकि इस्राएल के लिए भारत एक विशाल, स्थिर और भरोसेमंद बाजार है, खासकर जब यूरोपीय संघ जैसे पारंपरिक बाजारों में राजनीतिक प्रतिबंध बढ़ रहे हैं।

नवंबर 2025 में हस्ताक्षरित नया रक्षा सहयोग MoU bl साझेदारी को नया आयाम देता है, जिसमें AI, साइबर सुरक्षा, संयुक्त उत्पादन और कॉन्वेंट-सिद्ध तकनीक का विशेष उल्लेख है।

भारत- इस्राएल सम्बन्धों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि— भारत ने वर्ष 1950 में इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, किंतु लंबे समय तक दोनों देशों के सम्बन्ध सीमित और औपचारिक बने रहे। इसका प्रमुख कारण भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, अरब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और फिलिस्तीन समर्थक दृष्टिकोण था।

हालाँकि, भारत और इस्राएल के बीच सैन्य सहयोग के बीज 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान ही पड़ चुके थे, जब इस्राएल ने भारत को सैन्य सहायता प्रदान की। 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी इस्राएल ने गुप्त रूप से भारत की सहायता की। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन और वैश्वीकरण के बाद भारत की विदेश नीति अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी बनी।

वर्ष 1992 में भारत और इस्राएल के बीच पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए। इसके बाद दोनों देशों के सैन्य सम्बन्धों में तीव्र गति से विस्तार हुआ और इस्राएल भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार बनकर उभरा।

1948-1992: भारत ने इस्राएल को मान्यता तो दी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं बनाए। शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान भारत अरब देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता रहा। फिर भी, 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965/1971 के भारत-पाक युद्धों में इस्राएल ने गुप्त रूप से हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराए।

1992 के बाद: राजनयिक संबंध स्थापित होने के साथ ही रक्षा सहयोग शुरू हुआ। 1996-2000 के बीच Phalcon AWACS और Barak-1 मिसाइल जैसे बड़े सौदे हुए।

2014 के बाद (मोदी युग): पीएम मोदी की 2017 की इस्राएल यात्रा (पहली भारतीय पीएम की यात्रा) ने इसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। 2014-2025 के बीच रक्षा सौदों का मूल्य 10-12 अरब डॉलर से अधिक अनुमानित है।

सैन्य सहयोग के प्रमुख क्षेत्र— रक्षा उपकरण और हथियार प्रणालियाँ: इस्राएल आज भारत के शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस्राएल से अनेक उन्नत हथियार प्रणालियाँ प्राप्त की हैं। इनमें प्रमुख हैं:

क. बराक-1 और बराक-8 मिसाइल रक्षा प्रणाली: जो एक स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेरॉन और सर्चर मानवरहित विमान (ड्रोन), फाल्कन एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) आदि, इन प्रणालियों ने भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की युद्धक क्षमता, निगरानी शक्ति और रक्षा तैयारियों को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।

ख. मिसाइल और वायु रक्षा सहयोग: भारत-इस्राएल सैन्य सहयोग का सबसे सफल उदाहरण बराक-8 मिसाइल प्रणाली है। यह परियोजना भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (क्वेट) और इस्राएल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई। बराक-8 प्रणाली हवाई हमलों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और अन्य आधुनिक खतरों से रक्षा करने में सक्षम है। इसने भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान की है।

ग. ड्रोन और निगरानी तकनीक: आधुनिक युद्ध में ड्रोन और निगरानी प्रणालियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस्राएल इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। भारत ने सीमा निगरानी, आतंकवाद-रोधी अभियानों और खुफिया सूचना संग्रह के लिए इस्राएली ड्रोन तकनीक को अपनाया है। पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर निगरानी के लिए इस तकनीक ने भारत की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।

घ. आतंकवाद-रोधी सहयोग और खुफिया साझेदारी: भारत और इस्राएल दोनों ही आतंकवाद से गहराई से प्रभावित रहे हैं। इस कारण आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण, शहरी युद्ध तकनीक, विशेष बलों के प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग विकसित हुआ है। इस्राएल की आतंकवाद-रोधी रणनीतियों और तकनीकी अनुभवों से भारत को आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिला है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक



सामरिक और भू-राजनीतिक विश्लेषण- भारत-इस्राएल सैन्य सम्बन्ध केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव भी है। मध्य-पूर्व की अस्थिरता, ईरान की भूमिका, अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय रणनीतिक समझ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में यह साझेदारी महत्वपूर्ण बन गई है। भारत को इस्राएल से अत्याधुनिक रक्षा तकनीक प्राप्त होती है, जबकि इस्राएल को भारत जैसा विशाल और स्थायी रक्षा बाजार मिलता है। यह सहयोग शक्ति संतुलन की दृष्टि से भारत की स्थिति को मजबूत करता है।

'मेक इन इंडिया', आत्मनिर्भर भारत और सैन्य सहयोग- भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस्राएल के साथ संयुक्त उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और अनुसंधान सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में इस्राएली रक्षा कंपनियों की भागीदारी से न केवल रोजगार सृजन हो रहा है, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता भी सुदृढ़ हो रही है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ- यद्यपि भारत-इस्राएल सैन्य सम्बन्ध मजबूत हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- अरब देशों और ईरान के साथ भारत के पारंपरिक सम्बन्धों का संतुलन।
- नैतिक प्रश्न है और कुछ विश्लेषकों का मत है कि भारत-इस्राएल के हथियारों का उपयोग गाजा जैसे संघर्षों में होने से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है।
- प्रतिस्पर्धा भी, अमेरिका और फ्रांस से भी उन्नत तकनीक प्राप्त हो रही है, जिससे इस्राएल की हिस्सेदारी पर असर है।
- क्षेत्रीय प्रभाव भी है कि इसे पाकिस्तान इसे सामरिक असंतुलन मानता है।
- रक्षा आयात पर अत्यधिक निर्भरता।
- पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण की सीमाएँ।
- क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक दबाव।

इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाई है।

भविष्य की संभावनाएँ- भविष्य में भारत-इस्राएल सैन्य सहयोग के और विस्तार की प्रबल संभावनाएँ हैं। विशेष रूप से:

- साइबर सुरक्षा।
- अंतरिक्ष आधारित सैन्य तकनीक।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित हथियार प्रणालियाँ।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण।

ये सभी क्षेत्र दोनों देशों के सैन्य सम्बन्धों को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। 2025 के अंत में भारत ने 1000 SPICE किट्स, Air LORA, Ice Breaker मिसाइलों के सौदे मंजूर किए। इस्राएल यूरोप के प्रतिबंधों के बाद भारत को प्राथमिक विनिर्माण आधार बनाने की योजना बना रहा है।

नवंबर 2025 MoU के बाद सह-उत्पादन पर विशेष जोर: AI, साइबर, ड्रोन स्वार्म, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो चुकी है।

वर्तमान स्थिति (2025-2026), नवंबर 2025 MoU रक्षा सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित। मुख्य क्षेत्र: संयुक्त R&D, प्रशिक्षण, सह-निर्माण, AI-साइबर, आतंकवाद विरोधी सहयोग।

Aero India 2025 में इस्राएली कंपनियों (Rafael, IAI, Elbit) की भारी भागीदारी।

Adani & Elbit JV (हैदराबाद): Hermes-900 आधारित ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन।

सैन्य विश्लेषण: लाभ एवं सामरिक महत्व-

भारत के लिए लाभ:

उन्नत तकनीक त्वरित उपलब्धता- इस्राएल की कॉम्बेट-सिद्ध तकनीक (गाजा, लेबनान, ईरान संघर्षों से प्रमाणित)।

रूस पर निर्भरता में कमी- 2008-2024 में इस्राएल भारत के रक्षा आयात का 9-13% आपूर्तिकर्ता।

आत्मनिर्भर भारत- संयुक्त उत्पादन से तकनीक हस्तांतरण (Barak & 8, Spike, Drishti-10)।

चीन के विरुद्ध असममित क्षमता- ड्रोन, सेंसर, EW, लोइटरिंग मुनिशन।

मल्टी-लेयर एयर डिफेंस- Mission Sudarshan Chakra में इस्राएली तकनीक महत्वपूर्ण।

इस्राएल के लिए लाभ:

स्थिर एवं बढ़ा बाजार- भारत ने 2020-2024 में इस्राएल के कुल रक्षा निर्यात का 34-37% लिया।

संयुक्त R&D लागत में कमी- भारत का विशाल उत्पादन पैमाना।

एशिया में विस्तार- भारत के माध्यम से अन्य एशियाई देशों में पहुँच।

राजनीतिक समर्थन- भारत की तटस्थता/समर्थन (गाजा मुद्दे पर)।

निष्कर्ष- यह कहा जा सकता है कि भारत और इस्राएल के बीच सैन्य सम्बन्ध साझा सुरक्षा हितों, व्यावहारिक रणनीति और तकनीकी सहयोग पर आधारित हैं। यह साझेदारी भारत की रक्षा क्षमता, सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करती है। आने वाले समय में यह सैन्य सहयोग और अधिक गहन, व्यापक तथा बहुआयामी होगा।

भारत-इस्राएल सैन्य संबंध अब व्यापारिक लेन-देन से आगे बढ़कर रणनीतिक गठजोड़ का रूप ले चुके हैं। यह साझेदारी दोनों देशों की आतंकवाद विरोधी लड़ाई, उन्नत तकनीकी आवश्यकताओं और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है। 2025 का नया डब-और संयुक्त उत्पादन की दिशा में कदम दर्शाते हैं कि आने वाले दशक में यह साझेदारी और गहरी होगी, जिसमें I-संचालित युद्ध, ड्रोन स्वार्म, साइबर रक्षा और मिसाइल तकनीक प्रमुख होंगे।

यह गठजोड़ न केवल दोनों देशों की सैन्य क्षमता बढ़ाता है, बल्कि इंडो-पैसिफिक और मध्य पूर्व में एक नए प्रकार की रणनीतिक संतुलन शक्ति भी बनाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमारस्वामी, पी. आर. (2015). India-Israel Relations. Oxford University Press.
2. Foundation for Defense of Democracies (FDD), Israel and India Strengthen Defense Ties, 2025.



3. The Jerusalem Post, India & Israel defense ties built on innovation and trust, 2025.
4. Press Information Bureau (PIB), Govt.of India, "रक्षा सहयोग पर भारत-इज़राइल संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक", 2025.
5. SIPRI Arms Transfers Database (2020-2025 डेटा)।
6. Army Technology, "India and Israel boost defence cooperation with new MoU", 2025.
7. Middle East Monitor, "Arms, silence and alignment: The moral and geopolitical cost of India & Israel military ties", 2025.
8. IOSR Journal of Humanities and Social Science, "Diplomacy Beyond Boundaries: India-Israel Strategic Partnership In The Modi Decade (2014-2025)", October 2025.
9. ORF Hindi, "एशिया... इज़राइल का नया रक्षा बाजार", 2025.
10. The Economic Times @ AI & Monitor @ Breaking Defense (विभिन्न 2024-2025 लेख)।
11. Begin & Sadat Center for Strategic Studies, विभिन्न विश्लेषण 2025.
12. Cohen, S. (2018), Israel Security Doctrine. Tel Aviv University Press.
13. Ministry of Defence, Government of India. Annual Defence Report.
14. DRDO- Missile Systems and Defence Technology Reports.
15. SIPRI Yearbook (विभिन्न वर्ष).
16. पंत, हर्ष वी. (2019), भारतीय विदेश नीति. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
17. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस (रक्षा एवं विदेश नीति से संबंधित लेख)।
